just want to highlight some of the points, Madam, if you permit me for a few minutes.

Madam, as you know, the national programmes are looked after by the Central Government and the other health programmes are looked after by the State Governments. Under the national programmes, we have the leprosy eradication programme, the malaria control programme and a few other national programmes. We are trying to help the State Governments through these programmes to control these diseases and trying to eradicate these diseases from our country. As there is time constraint, I don't want to elaborate and go into the details. We will definitely take note of all the suggestions which the hon. Members have made on all points.

As regards the family welfare programme, all the hon. Members have said that the explosion of population was a mojor problem in our country. From the Central Government side we are trying to give a boost to the family welfare programme, that is, on a voluntary basis. The success of this programme depends mainly on the active co-operation of the State Governments. I would like to mention about the achievements of some of the States in the country, that is Kerala, Tamil Nadu and Goa. They have performed very well in regard to family welfare programme. I would like to draw the attention of the House to the major States, that is, U.P., Bihar and Rajasthan. The performance of Rajasthan in the field of family welfare programme is not satisfactory. Their performance compared to other States is very poor. I am sure all the Members, in their representative capacity, would definitely try to address themselves to this national programme. If we fail to control population explosion in our country, it will definitely affect our other national programmes. It will affect our economic programmes also. Some lady Members expressed their concern about the methods of family planning. We have taken note of all their suggestions. We have taken more of all their suggestions. We will definitely look into their suggestions, madam, a few days back a copy of the draft National Population Policy was laid on the Table. This House will deliberate upon the formulation of the National Population Policy of our country. The Government would certainly be guided by the valuable suggestions of the hon. Members . With these few words, I once again assure all the hon. Members that we have taken note of all their suggestions and as far as possible we will try to implement them in our future programmes. Thank you.

THE TRANSPLANTATION OF HUMAN ORGANS BILL, 1993

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): Madam, I move:

> "That the following amendments made by the Lok Sabha in the Transplantation of Human Organs Bill, 1993, be taken into consideration, namely:—
>
> *ENACTING FORMULA*
>
> 1. Page 3, Line 1—*for* "Forty-fourth" *substitute* "Forty-fifth"
>
> *CLAUSE—1*
>
> 2. Page 3, line 6—*for* "1993" *substitute* "1994"

The question was put and the motion was adopted.

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR: Madam, I move:

"That the amendments made by the Lok Sabha in the Bill be agreed to."

The question was put and the motion was adopted.

I STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE PUNJAB MUNICIPAL CORPORATION LAW (EXTENSION TO CHANDIGARH)ORDINANCE, 1994.

II THE PUNJAB MUNICIPAL CORPORATION LAW (EXTENSION TO CHANDIGARH) BILL, 1994

उपसभापतिः कृष्ण लाल शर्मा। शर्मा जी, संक्षेप में बोल दीजिए, चंडीगढ़ के साइज़ के हिसाब से और पंजाब की समस्या को ध्यान में रखते हुए।

डा॰ घुरली मनोहर जोशीः (उत्तर प्रदेश): लेकिन बिल चंडीगढ़ के साइज़ के हिसाब से नहीं है।

श्री कृष्ण लाल शर्मा (हिमाचल परदेश): उपसभापति महोदया, मैं निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हूं कि:

> "यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 24 मई, 1994 को प्रख्यापित पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्यांक 7) का निरनुमोदन करती है।"

उपसभापति महोदया, मैं इसके बारे में अपनी बात संक्षेप में कहना चाहता हूं और दो-तीन मुद्दों में उसे समाप्त कर दूंगा।

यह जो अध्यादेश जारी करने का तरीका है और यह जो संविधान की धारा—123 का बार-बार इस ढंग से दुरुपयोग किया जाता है, यह ठीक नहीं है, इतना ही नहीं पूरा एक वर्ष दिया गया, जब यह 74वां संविधान संशोधन पारित हुआ, उसके बाद एक वर्ष पूरा मिला है किन्तु बिल्कुल सिचुऐशन पोइंट पर आकर और वह भी इतने उपहासजनक तरीके से यह विधेयक लाया गया है। संसद के एक सदन का सत्रावसान करवाया गया, अध्यादेश जारी किया गया और फिर से दोबारा सत्र को बुलाने का आदेश जारी हुआ। अब यह धारा-123 क्या इसलिए है? सरकार की अपनी जो इनएफिशिएंसी है, उसकी जो गल्तियां हैं तथा उसका जो संसदीय विभाग के जो मंत्री हैं उनको जो दंड देना चाहिए, उनको देने के बजाए यह लोकतंत्र से बार-बार खिलवाड़ क्यों किया जाता है। मैं समझता हूं कि यह एक कारण इस बात के लिए पर्याप्त है कि सदन को इस अध्यादेश का निरनुमोदन करना चाहिए। ऐसा यह एक ही उदाहरण नहीं है, कई उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त इसके निरनुमोदन के लिए जो मैं कह रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि इसके बारे में सरकार को यदि यह अध्यादेश पास करवाना था, तो मैं समझता हूं कि इसको इस सत्र में लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह तो मानसून सत्र में भी लाया जा सकता था। हम तब इसको पास कर सकते थे । अभी ऐसा लगता है कि कोई काम बचा नहीं तो चलो यही कर दो। जब कोई अध्यादेश जारी होता है तो अगले जो रेग्यूलर सेशन में पारित करते हैं। अब हम इसको पारित कर रहे हैं। हमारे विधि मंत्री यहां बैठे हैं। अगर इस तरह से यह सारी चीजें की जाएंगी और अपनी गल्तियों का और अपनी कमियों का अगर सदन को दंड देंगे और सदन को हम गुमराह करेंगे या गलत चीजें बताएंगे तो मैं समझता हूं कि यह शोभनीय नहीं है। अतः इसके बारे में विचार हो कि क्यों इस प्रकार से यह अध्यादेश जारी किया गया और क्यों इसके बारे में एम्बूवल की यह स्थिति आई?

दूसरी एक बात है। चंडीगढ़ पर इसका अब हम विस्तारण कर रहे हैं। चंडीगढ़ यू॰टी॰ की स्थापना 1966 में हुई। 1966 से लेकर 1994 तक 28 साल में वहां पर कोई भी प्रतिनिधि संस्था नहीं है। केवल लोक सभा का वहां पर चुनाव होता है। वहां कोई कार्पोरेशन नहीं, कोई म्यूनिस्पल कमेटी नहीं, कोई और संस्था नहीं जिसमें कि वहां चंडीगढ़ मे रहने वाले लोग यह महसूस करें कि वह भी कोई वहां के कामकाज में भागीदार हैं। कोई किसी तरह की वहां की व्यवस्था में, वहां के जितने भी काम हैं, बिजली है, पानी है, सेनिटेशन आप लोगों की तकलीफें हैं, इसके बारे में वहां के कोई प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लें या लोगों के मन में यह भावना हो कि हमारे प्रतिनिधि बैठकर इस पर कोई निर्णय कर रहे हैं, इस तरह की कोई भी बात पिछले 28 साल से वहां पर नहीं है। अब विचित्र बात यह है कि 28 साल के बाद एक अधिनियम लाया जा रहा है। अब मैं तो कहूंगा कि इसको कार्पोरेशन कहना चाहिए, नगर निगम कहना चाहिए, इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता। यह इतना क्रूर उपहास है। इस चंडीगढ़ के नगर निगम में केवल 10 लोग इलेक्टेड होंगे और इसमें 9 लोग नॉमिनेटेड होंगे। अन्य जगहों पर वार्ड बनते है, वार्डों में परिसीमन होता है। लेकिन चंडीगढ़ एक ऐसी जगह है जहां पर बाकायदा पहले से सैक्टर बने हुए हैं।

यहां पर 47 सैक्टर हैं, 3 सैक्टर अभी बन रहे हैं लेकिन इतना बड़ा एक नगर जहां पर कि कोई प्रतिनिधि संस्था नहीं है, कोई विधानसभा नहीं है, कोई और चीज नहीं है तो वहां इसको इतना सीमित कर देना और फिर नॉमिनेटेड लोगों को वहां पर वोटिंग का अधिकार देना, यह तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल एक मज़ाक बनाया

जा रहा है। जो भी चुने हुए लोग होंगे, उनके ऊपर नॉमिनेटेड लोगों को बिठा दिया जाए। यह तो 74वें संशोधन की भावना नहीं है। अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर रहे हैं और लोगों को ताकत देना चाहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो चुने हुए लोग हैं, उनके ऊपर हम नॉमिनेटेड लोगों को बिठा दें। शासन वही चलाएं और चुने हुए लोग केवल मुंह देखते रहें और उनकी हां में हां मिलाते रहें। मैं समझता हूं कि जो यह इस तरह की बात की जा रही है, यह एक तरह का खिलवाड़ है।

अगर हम एक-एक चीज को देखें, एक-एक धारा को देखें तो जो संशोधन किए जा रहे हैं, उसकी कमियाँ नजर आती हैं। जैसे धारा 47 है। इसमें प्रावधान है कि नगर निगम के आयुक्त की नियुक्ति प्रशासक करेगा, प्रशासक की नियुक्ति केन्द्र सरकार करेगी और बाकी सारी नियुक्तियाँ आयुक्त करेगा तो फिर नगर निगम क्या करेगा? अगर उसने नियुक्तियाँ भी नहीं करनी है, कोई काम भी नहीं करना है तो नगर निगम के जिम्मे आखिर काम क्या होगा? क्या यह धारा लोकतंत्र को कोई शक्ति देने वाली धारा है कि कमिश्नर को ऐडमिनिस्ट्रेटर एपाइंट करेगा और ऐडमिनिस्ट्रेटर को सेंट्रल गवर्नमेंट एपाइंट करेगी और कर्मचारियों की एपाइंटमेंट्स और सर्विस कंडीशंस कमिश्नर तय करेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इस अधिनियम को पास करना उचित नहीं है जब तक आप इसमें उचित संशोधन नहीं करते और उचित परिवर्तन नहीं करते।

इसमें कितनी ही बातें नहीं हैं कि जिससे कि लोगों को उपयुक्त प्रतिनिधित्व मिले, जो नगर निगम बने उसको यह शक्ति मिले कि वह सारे कर्मचारियों की नियुक्तियाँ करे। अभी जो व्यवस्था है उसके अनुसार जो महापौर होगा, मेयर होगा, उसको तो कोई पावर नहीं है और वह हमेशा कमिश्नर के मुंह की तरफ देखेगा और कमिश्नर, ऐडमिनिस्ट्रेटर के मुंह की तरफ देखेगा। मुझे लगता है कि इस तरह के अधिनियम को लाकर हमें लोकतंत्र से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा कि यह धारा 123 का दुरुपयोग है।

हम इस अध्यादेश के द्वारा इसको अधिनियम में परिवर्तित कर रहे हैं। इसमें अगर एक-एक धारा को हम देखें तो उसमें से यह निकलता है कि 74वें संशोधन की जो भावना है, हम उसको समाप्त कर रहे हैं। लोगों तक जो सारी शक्ति जानी चाहिये, वह नहीं दे रहे हैं और इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। यह कोई चुनी हुई संस्था नहीं बनेगी बल्कि ऐसी होगी कि जिस पर शासन द्वारा नियुक्त लोग या नामांकित लोग शासन करेंगे और चुने हुए लोग मूक दर्शक बनकर रह जाएंगे। इसलिए इसमें किसी का कोई इंट्रस्ट नहीं रहेगा। कोई सदस्य वहां नहीं जाएगा, वहां जाकर क्या करेगा अगर उसको कुछ अधिकार नहीं है तो।

इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी कुछ इसमें बिगड़ा नहीं है। सरकार इस बारे में यह आश्वासन दे कि इसमें आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे और इसको एक लोकतांत्रिक स्वरूप दिया जाएगा। मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता लेकिन मुझे लगता है कि एक-एक चीज आपको देखनी चाहिये। इसका जो वित्तीय प्रबंध होगा, जो फाइनेंस कमीशन बनेगा, वह भी सरकार के अधीन रहेगा।

इस में भी महापौर का कोई अधिकार नहीं होगा। सारी चीजों और सारे स्वरूप को देखते हुए मुझे लगता है कि मैंने जो प्रस्ताव रखा है, उस को फिर आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि इस अध्यादेश को जो 24 मई 1994 को राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया, उस का निरनुमोदन करें। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जब तक इस विधेयक को पूरा लोकतांत्रिक स्वरूप नहीं दिया जाता तब तक इसको सदन में न लाएं और इस तरह से चंडीगढ़ के लिए जिसे पहले ही इस बात की शिकायत है कि 1966 से लेकर अब तक उन को कोई अधिकार नहीं दिया गया, कोई प्रतिनिधि संस्था नहीं दी गई, अब ऐसी कठपुतली संस्था उन को दी जा रही है दें जिसके हाथ में कोई अधिकार नहीं है।

महोदया, मैं एक बात और कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। चंडीगढ़ के बारे में अभी भी तलवार लटक रही है, एक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है कि चंडीगढ़ का क्या होगा। आज 28 साल के बाद भी चंडीगढ़ वहीं रहेगा, पंजाब में जाएगा या हरियाणा में जाएगा, क्या होगा। इसका पता नहीं। जो कुछ भी हो, मैं इस बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि नगर निगम बनने के बाद सरकार इस बात को ध्यान में रखे कि चंडीगढ़ के बारे में जो कोई भी निर्णय करना है उस मैंइस नगर निगम के द्वारा भी प्रस्ताव पारित होना चाहिये। यह जो नगर निगम आप वहां पर स्थापित करने जा रहे हैं, यह चंडीगढ़ की प्रतिनिधि संस्था होगी। इस की राय लिए बिना चंडीगढ़ के बारे में कोई फैसला करना यह सर्वथा अनुचित होगा। थोड़ा सा भी जो अधिकार आप उन को दे रहे हैं, प्रतिनिधि चुनकर जो वहां आएंगे उन को यह अधिकार होना चाहिये कि चंडीगढ़ के बारे में जो वह भावना व्यक्त करें उसके

अनुसार चंडीगढ़ का भविष्य में आप निर्णय करें और वह चंडीगढ़ नगर निगम की राय और प्रस्ताव के द्वारा हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव के बारे में गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस बिल के मैरिट और टेक्निकल रीजन्स के कारण भी मैं इस बिल का विरोध करता हूं और अपनी बात सदन के सामने रखते हुए अनुरोध करता हूं कि इस का निरनुमोदन किया जाए। धन्यवाद।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S.B. CHAVAN) : Madam Deputy Chairman, I beg to move:

> "That the Bill to provide for the extension of the Punjab Municipal Corporation Act, 1976 to the Union Territory of Chandigarh, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The Union Territory of Chandigarh came into existence on 1.11.1966 under the- Punjab Reorganisation Act, 1966. The city of Chandigarh hosts the capitals of the States of Punjab and Haryana and is also the headquarters of the Administration of the Union Territory of Chandigarh. The development and regulation of the city of Chandigarh is controlled by the Capital of Punjab (Development and Regulation) Act, 1952. So far this city does not have a Municipal Corporation. This Bill seeks to provide Chandigarh its first Municipal Corporation as mandated now, by Part IX-A of the Constitution. The Bill mainly seeks to provide a Municipal Corporation for Chandigarh by extending the Punjab Municipal Corporation Act, 1976 with suitable exceptions and modifications to the Union Territory of Chandigarh.

Part IX-A has been added to the Constitution by the Constitution (Seventy-fourth Amendment) Act, 1992 with effect from 1.6.1993. With the insertion of Part IX-A, municipalities in States and Union Territories are to be constituted in terms of provisions of the Constitution. Article 243ZB of the Constitution provides that Part IX-A shall also apply to the Union Territories subject to such exceptions and modifications as may be directed by the President by notification.

The Government of Punjab enacted the 'Punjab Municipal Corporation Act, 1976' for establishing Municipal Corporations in large urban agglomerations in the State. This Act repealed, among others, the Punjab Municipal Act, 1911. The Provisions of 1976 Act were, however, not made applicable to the Union Territory of Chandigarh. Thus certain provisions of the Punjab Municipal Act, 1911, are still applicable to Chandigarh.

The city of Chandigarh has the following special characteristics calling for special treatment:

(1) It is the capital of the State of Punjab as well as of the State of Haryana and is also the headquarters of the Union territory of Chandigarh. Such a situation does not exist anywhere in India. It is necessary to make special provisions with a view to providing for this special character of the city till such time as the political future of the city is decided.

(2) Le Corbusier's Chandigarh is one of the first planned cities of India and the Capital Project is still under execution. In fact, new phases are being planned for the future development of the Territory. It is essential that nothing should be done which would distort the aesthetics, the planner's vision and the architectural and design concept and the master layout plan underlying the basic character of Chandigarh.

(3) Chandigarh has to be given special treatment due to its transitional status as the common capital of Punjab, Haryana and UT of Chandigarh.

In view of the above special characteristics, it would be appreciated that any scheme for the governance of this area based on the conventional pattern of representative local self-Government would be unworkable.

In view of the above it is proposed that the application of provisions of part IX-A of the Constitution in respect of the following articles may be modified to meet the above said special requirements:

(1) With regard to article 243R on Composition of Municipalities, it is proposed to have nominated members also. Thus the composition of the Corporation will have the following elements:

(a) 20 members to be directly elected.

(b) Nine members to be nominated (with voting right) by the Administrator.

(c) Chairperson to be elected by the full House including the nominated members from amongst the 20 elected members.

(2) With regard to article 243T on Reservation of Seats and office of Chairperson, it may be stated that in the Union Territory of Chandigarh no tribe or tribal community has been specified as "Scheduled Tribes", and thus there is no question of any reservation in their favour. In the case of Scheduled Castes and women, the provisions of the Constitution are to be followed in respect of seats to be filled by direct election. No reservation in favour of women belonging to backward classes is, however, provided. There would also be no reservation of seats in the case of nominated members. The office of Chairperson of the Corporation, to be known as "Mayor", shall be reserved in favour of a member who is a woman for the first and fourth year of the Corporation and in favour of a member belonging to the Scheduled Castes in the third year of the Corporation.

(3) With regard to article 243V on disqualification for membership, it is proposed that disqualification, if any, relating to "Office of Profit" for the purposes of election to the House of the People may not be made applicable to the members to be nominated by the Administrator.

(4) With regard to article 243W on Functions, it may be stated that all the functions included in the Twelfth Schedule of the Constitution and in the Punjab Municipal Corporation Act, 1976 as amended up to date are to be made the responsibility of the Municipal Corporation, except the following which are proposed to be retained by the Administration:

(a) Urban planning, including town planning.

(b) Regulation of land use and regulation of construction of buildings.

(c) Such important parks and stadia as may be specified by the Administrator.

(5) The Finance Commission and the Election Commission constituted in the National Capital Territory of Delhi are proposed to be made responsible also for the functions in respect of the Union territory of Chandigarh.

The Punjab Municipal Corporation Law (Extension to Chandigarh) Ordinance, 1994 was promulgated by the President on 24th May, 1994 to fulfil the Constitutional obligation. The ordinance mainly extended the Punjab Municipal Corporation Act, 1976 as amended from time to time with some exceptions and modifications to the Union territory of Chandigarh. The present Bill is to replace the said Ordinance.

Madam, I am sure that this Bill will be welcomed by all sections of this august House. I commend this Bill for the consideration of the House.

The questions were proposed.

SHRI VENOD SHARMA (Punjab) : Madam, I stand here to support the Bill.

Chandigarh, as rightly mentioned by

the hon. Home Minister, has a unique position of being the capital of two States. Chandigarh was conceived of by Pt. Jawaharlal Nehru as a modern city of this country but as the capital of Punjab at that time. In 1966 Chandigarh became a Union Territory when Punjab and Haryana were created as linguistic States. For the last 28 years there was no elected body to supervise the local affairs of the city. Chandigarh as such is a beautiful city, and it is rightly known as the "City Beautiful". With educational institutions, with people from all over the country, who have settled over there, it has taken the shape of a metropolitan city. I thank the hon. Minister and congratulate him for bringing in this Bill, the Punjab Municipal Corporation Law (Extension to Chandigarh) Bill, 1994 which has been passed by the Lok Sabha for the extension of the Punjab Municipal Corporation Act, 1976.

I will take only a little time to speak about Chandigarh. In Chandigarh there are certain aspects which probably have not been taken into consideration. The people who reside in Chandigarh are literate people. Probably, Chandigarh is amongst the few Union Territories and States which have the highest percentage of literacy.

I will further congratulate the Minister for increasing the elected seats from ten to twenty. But, at the same time, nine Members are to be nominated to the Corporation by the Administrator. I have not understood one particular thing, why nine Members with voting rights should be nominated by the Administrator from amongst the persons who are eminent or distinguished in public affairs or those who have special knowledge or practical experience in respect of municipal administration. Will these nine Members be nominated from Chandigarh or from outside the area of Chandigarh? This has not been specified in this Bill. I have no objection to that also.

AN HON. MEMBER: May be from Kanyakumari.

SHRI VENOD SHARMA: I want to know only this, Madam, through you. while the people of Chandigarh will be electing 20 Members, the nine Members with voting rights, who will be nominated, will be influencing the decisions of the Corporation. It is a kind of aspersion on the people of Chandigarh, a kind of aspersion on the intelligentsia of Chandigarh that they will not be able to carry on the business of the Corporation.

Further, section 6 lays down:

> "Seats shall be reserved for women belonging to the Schedules Castes, from amongst the seats reserved under sub-section (4) of section 5 for the Scheduled Castes, the number of such seats being determined by the Administrator by an order published in the Official Gazette, which shall not be less than one-third of the total number of seats reserved for the Scheduled Castes."

It is heartening to note that one-third of the total seats will be reserved for women and that separate "constituencies will be marked for women to contest from those constituencies. It is in consonance with this Government's spirit of giving opportunities to women to participate in the governance of the local affairs, and I congratulate the hon. Minister. But, at the same time, it has been said that for the first term and for the third term a woman would be the elected Mayor.

I do not know what will be the scenario if a particular political party gets 12 successful seats out of 20 seats and unfortunately no woman candidate is elected out of those 12 successful seats. What scenario will emerge? Who will be elected as Mayor? In that case probably we would have to bargain and find out from which party the woman will come and become Mayor.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Why do you assume *a* woman will not be elected?

SHRP VENOD SHARMA: I never said woman will not be elected. One-third of the total seats have been reserved for women. From those seats woman candidates will be elected and sent to the Corporation.

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा): फिक्र मत कीजिये जिनकी मेजोरिटी आएगी उनके पास वूमेन है।

SHRI VENOD SHARMA: I was only worried about the BJP, because BJP does not have any woman candidate. I am not worried about my party.

श्रीमती सुषमा स्वराज: आप हमारी चिन्ता क्यों करते हैं विनोद जी (व्यवधान)

SHRI VENOD SHARMA: I know Krishan Lai Ji was speaking as if he has not visited the town. It seems you have not visited the town for the last ten years.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Why have I not visited the town?

जिस शहर में मैंने 15 साल बिताए हैं और आप कह रहे हैं ...(व्यवधान)

SHRI VENOD SHARMA: I say in the last ten years you must have visited the town for a day or two, but you are not living there. So, you do not know what is happening in the town.

श्रीमती सुषमा स्वराज: हम पहला मेयर बनाएंगे, विनोद जी।

SHRI VENOD SHARMA: Anyway, if you feel that you want to update your knowledge about the city, I will do that. Madam, as has rightly been said by the Hon. Minister and pointed out by the hon. Member, Shri K.L. Sharma, it has not been decided yet as to what fate Chandigarh will meet tomorrow. But there is nothing wrong to have our own Corporation; there is nothing wrong if the people participate in the affairs of the day-to-day running of that city and it is the first time in the last 28 years when the people of Chandigarh will get an opportunity to elect a candidate apart from a Member of Parliament in the Lok Sabha. The people have been looking towards it and the people, particularly the people of Chandigarh,are thankful to this Government for bringing in this Bill. But as the hon. Minister has said looking to the unique situation of Chandigarh being the capital of two States, there are certain provisions which have been made while giving the powers to the Corporation. What has been mentioned under Chapter 9(A) of the Constitution, certain powers have been diluted. While it was said that urban planning, including town planning, has been taken away from the Corporation's control.

My concern is that urban planning including town planning has been taken away from the corporation. Regulation of land use and construction of,building has been taken away from the control of the corporation. Slum improvement and upgradation also has not been included in the jurisdiction of the corporation. I may mention it here that nearly 20 per cent of the population of the town still lives in slums. The people who came to Chandigarh to construct it have settled down there. They have been living there for the last thirty years or forty years. They are eligible citizens of the town like other people who have come after 1952. But ironically those slum dwellers have not been provided with a shelter in their town. Certain efforts were made by the administration but it has not taken the shape, the way it should have taken. Today, if the local representative of the people do not have any say for the resettlement of those people, then, how can the slum dwellers be settled in the right kind of a place? How can justice be done to those people? Though the Bill is in consonance with the feelings of the people of that town but at certain level, at the local level, at the administration level, it looks as if they were losing something and they do not want to lose anything. They were living in that town for the last 28 years. Certain powers which should have been conferred in the Bill on the corporation has not been conferred.

Again I congratulate the hon. Minister for bringing forward this Bill. I appeal to

my colleagues to pass this Bill. Thank you.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA (Punjab): Madam Deputy Chairman, I rise to support the Punjab Municipal Corporation Law (Extension to Chandigarh) Bill, 1994, for one particular reason Chandigarh was denied a democratic right to run its own affairs. To me it appears to be a classic case of limited and guided democracy. Why I am calling it a guided democracy and a limited democracy because the powers that this Municipal Corporation would have would be very minimal; and they will be guided by the nominated members. I do not know whether there is any elected chamber in the world where nominated member would be sitting with elected members and exercise similar powers, howsoever they are eminent. But I consider it to be a case of a guided and limited democracy.

Before I actually go into the provisions of the Bill, I have strong reservations to express. As other colleagues of mine have said, Chandigarh was built and conceived to be a capital city for Punjab. It was built for Punjab. Every State in India, people in those States have a dream of their own capital. They would like to see what kind of capital they would like to have. I do support this Bill because for the past 26 years the people of Chandigarh did not have a democratic right to exercise their franchise. But the question is, Chandigarh does not belong to the people of Chandigarh alone. In fact, by bringing forward this Bill, the Government is taking away the rights of the Punjab Legislature, the rights of the people of Punjab because they have a dream 6f their own as to what kind of Chandigarh they would like to build. It was very unfortunate that political disputes went on occurring; and it could not be resolved. My hon. senior colleague, Mr. Sharmaji doesn't say that it belongs to Haryana. They did not claim it either. In any case, in any situation, this should go to Punjab. If the nominated members have to be there, it should be specified that members would be nominated only from Punjab areas not from Chandigarh because it is a city belonged to us, it is a city belonged to the people of Punjab. Unless an assurance is given by the Minister that Punjab is going to get Chandigarh, this is not going to be really a democratic institution. I do not agree with Mr. Venod Sharma that it is a democratic institution being set up to look after the people of Chandigarh. It has got a very limited power. A lot of capital project is ept separate. The major functions of a city are in terms of providing an infrastructure. All these things have been kept away from the corporation. If Chandigarh is integrated with Punjab, the people of Punjab feel the relevance of governing Chandigarh. So my request to the Government is that the nominated members must be from Punjab, not from Chandigarh. Chandigarh will elect its 20 members. This is my first suggestion.

THE DEPUTY CHAIRMAN: If Chandigarh is part of Punjab, then, the people of Chandigarh also should form part of Punjab.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: That is what I am saying. I am saying that until a decision is taken on Chandigarh, let the people of Punjab represent Chandigarh Corporation and guide its affairs in the overall context. This is my first suggestion.

Secondly, the Bill is talking about Chandigarh. I earnestly appeal to the hon. Home Minister that this is the right time to hand over Chandigarh to Punjab as Punjab has really achieved abnormally a normal situation today...*(Interruptions)*... That is what I am saying. You do not find a normal situation in many parts of the country. Punjab has really achieved abnormally a normal situation. I would request and appeal to the hon. Home Minister that a decision must be taken to hand over

Chandigarh to Punjab. In fact, people of Punjab are looking forward to such a decision.

Lastly, I would say...

Madam, I do support the Bill. But, if it is possible, do extend the power.

As Mr. Sharmaji has said, the Corporation does not have an appointing authority. All the appointments in the Corporation would be made by the Administrator. That again would be unfair to the Corporation. In fact, the Corporation has come into force on 26th May itself. In the next six months, there is not going to be an election. So, the Administrator of the Corporation would hire all the people, would make all the appointments before the elected Corporation is formed or constituted. So I would request that this particular aspect should not be ignored.

Lastly, Madam, I do not know whether it is really possible, but Chandigarh should be given special funds in this context because there are a lot of development activities taking place there. And Chandigarh is short of funds. I would request again that a special grant to Chandigarh be made. Thank you very much.

SHRI S.B. CHAVAN: Madam Deputy Chairperson, I must express my gratitude to all the hon. Members who have participated in the discussion and thank them for being very brief so that we may be able to pass the other ordinance which was promulgated by the President.

The circumstances under which the Ordinance had to be issued in this particular case are as follows. Before that, I am really surprised that every time an Ordinance is being brought, there is a set pattern of arguments. Specially, the BJP seems to have specialised in this. Over and over again, they go on repeating the same thing. *(Interruptions).* I can understand and appreciate that to the extent possible, we should try to avoid ordinances being issued. But if there are special reasons, I think that there is hardly any difficulty in accepting the position as it is obtaining. I am sure that hon. Members will be able to appreciate that. I do not know how Mr. Krishan Lal says that this could have waited till the Monsoon Session. I am sure that he is aware of the constitution (seventy fourth) amendment.

An according to that amendment, the Bill or the Ordinance has to be in consonance with the spirit of the Seventy-fourth Amendment and its time-frame was till 31st of May. The House was adjourned on 13th or 14th, I do not remember, but I got the proposal in the middle of May and thereafter it became a real difficulty for us that we had been writing to all the State Governments that they had better bring all these laws in consonance with the spirit of the Constitutional amendment. In the case of Central Government we ourselves are not in a position to do the same, and this extraordinary procedure had to be followed. You know how meticulous our Secretariats, both in Lok Sabha and Rajya Sabha, are. And I must also bring to the notice of the House that in spite of the Bills having been passed, more meticulous is our President who goes through very carefully, word by word, and he will never allow anything... *(interruptions)...*

THE LEADER OF OPPOSITION (SHRI SIKANDER BAKHT): I am sure, you mean it. It is not sarcastic.

SHRI S.B. CHAVAN: No, no; certainly I can never be sarcastic. So far as the personality of the President is concerned, I will be the last person to be sarcastic in this case. I am sorry if I have been misunderstood by the hon. Member. I can neither be sarcastic in the case of Speaker nor in the case of Chairman nor in the case of President. These are very high dignitaries who carefully go through all the issues and after scrutiny they take their own decisions. We may or may not agree; that is a different matter. If there had been any case for which the Ordinance

had to be promulgated and if, in spite of the House having been adjourned,—after all, these rules are meant for observing certain things which the Constitution has laid down—for any reason, say even by a lapse or for harmonising the legislation with the provisions of the Constitution, the House had to be adjourned, I do not find anything wrong. There can be no other case in which both Ordinance and prorogation would have been justified as in the case of these three which had been done and for which the special Session had to be called.

Madam, the next point made was very clear and after listening to the three speeches, I any more than satisfied that the nomination has been fully justified. The hon. Member, Mr. Krishan Lal Sharma said, "The future of Chandigarh should be decided after the Resolution on the Chandigarh Municipal Corporation is passed." One Member went to the extent of saying that if nominations are to be there, they should be only from Punjab. The fact is that such a divergence of opinion is there. Hon. Members, you will be surprised to know that when this Bill was drafted, it took me a considerable time to convince both the Chief Ministers of Punjab and Haryana that after the Constitution amendment they do not have any escape. They will have to have some kind of a legislation by which we will be able to justify, that after the Constitutional Amendment Bill, the kind of set-up which is required for the Chandigarh city; they will have to have some kind of a set-up by which we can have democratic elements as well as nominated elements for compromising so that they may not have any kind of apprehension in their mind that one section is going to be over the other. I am very surprised when some of the hon. Members went to the extent of saying that these nominated Members are going to guide all these elected Members.

6.00 P.M. I don't mean any disrespect to anyone. But all the nominated members will also be eminent people in their own right. Fortunately, Chandigarh has plenty of these people. There are plenty of people who are, in fact, eminent in their own right. If, by any chance, they would not like to go in for any election, can't you make use of the talent which is available there? So, I cannot commit myself that the nominated people are going to be either from Punjab or from Haryana or only from Chandigarh. But members will be nominated mostly from these areas. There should be no difficulty in having eminent people who will be able to assist. They will not guide. Even if they guide and if the elected members feel that they are being guided by them, there is no harm in having the guidance which is required. So, there need not be any kind of apprehension in the mind of anyone.

SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Why is this provision only in this Corporation?

SHRI S.B. CHAVAN: We will have to classify them after they are elected. This classification comes only after the elections take place. They are*going to be nominated for their eminence, knowledge and experience which they are having. With their presence, I believe, some kind of a balance will definitely be established. So far as the future of Chandigarh is concerned, I cannot possibly say anything about it. It is because of that only a new pattern has been adopted for Chandigarh. The political future of Chandigarh is still not decided. I can assure the hon. Members that we stand by the Rajiv Gandhi-Longowal accord and try to strike the kind of balance which had been prescribed in that accord that in *lieu* of Chandigarh something has to be given to Haryana and thus find some solution to the city. In *lieu* of Chandigarh, which is going to a particular side, how many villages or what areas are to be given to Haryanan is a matter which has to be decided politically.

Madam, I think I have covered the

majaor points which the hon. Members have made.

SHRI JAGMOHAN (Nominated): I have one clarification to seek. Is it not a fact that the nominated members are going to be nominated in consultation with the Chief Minister of Haryana and the Chief Minister of Punjab so that they may also have their say in the administration of the Union Territory? The capital of both the States is located in that area.

SHRI S.B. CHAVAN: I wouldn't commit myself, but at the same time you cannot rule out that possibility either. But they are going to be nominated. If I would have consultation only with the Chief Ministers of the two States, I know ultimately what is going to be the picture of the nominated members. The very purpose of nomination is to have some kind of a balance. If the intellectuals, who otherwise would not participate in the elecions, can be nominated and if they would do some service to the city, I think this is the proper time when these people should be given an opportunity. I think these were the main points which were made by the hon. Members.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: What about the powers of the Corporation?

SHRI S.B. CHAVAN: In fact, only three powers have been left with the administrator. All powers under the Twelfth Schedule, almost eighteen powers, are given to them. I have got the total list. Infrastructure which the hon. Member was mentioning is not correct. Infrastructure is going to be with the Corporation. Only planning and Building Regulation part of it and stadia and selected parks and a few other things are kept with the administrator because of the special feature of that city. The rest of the powers have been given to them. All the powers under the Punjab Municipal Act as amended up to 1976, barring these powers which have been kept with the administrator, are going to be given to the Corporation.

It is not correct. I am really surprised. The Commissioners are always appointed by the Government. Mr. Krishan Lal Sharma and some other Members wanted to know whether the Commissioner would be appointed by the Government or by the Administrator of that area. The Commissioner is the executive head of the administration. The candidates are selected by the UPSC. But if, for some reason or the other, the Public Service Commission is not mandatory for certain purposes, then the selection will be done by the Administrator. This kind of a practice where Class-Ill and Class-IV people need to be appointed by a committee, is not obtaining anywhere. This kind of power is not given to any committee. The committee has to be a policy-making body and according to the policy enunciated by a committee, it is for the Administrator or the Commissioner of the Corporation, who will be the executive head, to emplement the decision taken by the Corporation. With these words, I request Shri Krishan Lai Sharma to withdraw his Resolution. I also request the hon. Members to support this Bill.

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Madam, I would like to have one clarification. Mr. Minister, what is the difficulty in passing the slum improvement work to the Corporations? Is there any difficulty? The slum improvement work is done by the municipalities.

SHRI S.B. CHAVAN: This pattern has to be adopted because of the special atmosphere prevailing in that area.

श्री कृष्ण लाल शर्मा: मैं यह बात कहूंगा कि मंत्री जी ने इसको स्वीकार किया है कि वास्तव में जो इलेक्टिड लोग हैं, उनके अलावा वे कोई ऐसी व्यवस्था रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने नामिनेशन का प्रावधान किया है। मैं यह कह रहा था कि और भी इस देश में बहुत सारी कारपोरेशन्स हैं क्या किसी और कारपोरेशन

में इस तरह के प्रावधान हैं? इसके बारे में फिर वह धारा 71 में नियुक्तियों के बारे में साफ लिखा है कि इसमें सारी नियुक्तियां आयोग करेंगे और प्रशासक आयोग को नियुक्त करेंगे। मेरा आपसे सिर्फ यह निवेदन है, कि एक तो चंडीगढ़ को यह पाकेट एडीशन नगर निगम मत दीजिए, कारपोरेशन बहुत छोटा है और इतना बड़ा यह नगर है और उनके पास कोई दूसरी संस्था भी नहीं है, तो बिल्कुल छोटा यह बनेगा और इसको इतने कम अधिकार दे रहे हैं कि यह देने के बाद भी वास्तव में जो यह उद्देश्य है और मैंने कहा कि 74वां हमारा जो संविधान संशोधन है, उसकी भावना के अनुसार पूरा नहीं बैठता। मैं चाहता हूं कि आप इस पर आश्वासन दें और इसके आधार पर मैं अपने निरनुमोदन का प्रस्ताव वापिस कर लूंगा।

श्री एस०बी० चव्हाण: यह प्रेक्टिस दूसरे कारपोरेशन्स में नहीं है, मुझे मालूम है, नामिनेशन की, लेकिन मैंने अभी आपको समझाया है कि नामिनेशन के पीछे क्या भावना है हमारी। तो वह स्पष्टीकरण हमने दिया है और एप्वाइंमेंट के जितने भी अधिकार हैं वह सारी कारपोरेशन्स में, मैंने जो बात कही है वह सारे कारपोरेशन्स में एप्वाइंटमेंट कभी कमेटी के धू या कारपोरेशन्स के धू नहीं होते हैं, इतना मैं आपसे कह सकता हूं। तो वहां के हालात को देखते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसको वापिस ले लीजिए।

उपसभापति: आप वापिस ले रहे हैं? नहीं तो वोट हो जाएगा।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली): स्ट्रेंथ कम दिख रही है हमारी, इसलिए आप कह रही हैं कि वोटिंग हो जाएगी।

उपसभापति: अगर नहीं भी होती तो मुझे क्या फर्क पड़ता है।

श्री कृष्ण लाल शर्मा: फर्क तो पड़ता है आपको। अगर माहोल दूसरा हो तो फिर फर्क पड़ता है।

उपसभापति: चेयर को कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री सतीश अग्रवाल (राजस्थान): मैडम डिप्टी चेयरमैन, इस सैशन में हुआ क्या है? इंट्रोडक्शन के लिए सैशन बुलाया गया था और विदड्राअल ही विदड्राअल हो रहे हैं।

श्री कृष्ण लाल शर्मा: मैंने इसलिए यह निवेदन किया, उन्होंने सिद्धांत माना भी है, इसलिए मैं अपना यह निरनुमोदन का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

The Resolution was, by leave, withdrawn.

THE DEPUTY CHAIRMAN: These withdrawals are only of the Bills, Motions and Resolutions and not of the brown sugar.

The question is:

> "That the Bill to provide for the extension of the Punjab Municipal Corporation Act, 1976, to the Union Territory of Chandigarh, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

THE SCHEDULE

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Madam, I move:

1. "That at page 6, lines 21 to 25 be *deleted.*"

2. "That at page 6, lines 28 *for* the word "twenty" the word "thirty" be *substituted."*

The questions were proposed.

श्रीमती सुषमा स्वराज: धन्यवाद उपसभापति महोदया, मैंने इस विधेयक में दो संशोधन प्रस्तुत किए हैं। मेरा पहला संशोधन है कि पृष्ठ-6 पर अंकित संख्या 21 से संख्या 25 तक की पंक्तियां हटा दी जाएं। जैसा मैंने कहा कि यह मूल बिल में धारा-4 की उपधारा-3 की उपधारा-2 में लिखी गई हैं यह पंक्तियां। इन पंक्तियों में 9 सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान है। मैं उन पंक्तियों को पढ़े देती हूं:

> "Nine members with voting rights to be nominted by the Administrator, from amongst the persons who are eminent or distinguished in public affairs or those who have special knowledge or practical experience in respect of municipal administration."

उपसभापति महोदया, मेरा यह आरोप है कि इस विधेयक के माध्यम से जो लोकतांत्रिक ढांचा चंडीगढ़ के लोगों को सरकार दे रही है वह एक हाथ से देकर इन

शक्तियों के माध्यम से दूसरे हाथ से छिनने की बात कर रही है। मैं गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि दो-तीन बार उनसे यह सवाल पूछा गया, उन्होंने जो भी जवाब दिया उससे हम कंविंस नहीं हुए हैं। मेरा सीधा सा प्रश्न है कि इन 9 सदस्यों के मनोनयन का औचित्य क्या है? क्योंकि मैं आपकी जानकारी में एक चीज लाना चाहती हूं कि यह विधेयक चंडीगढ़ के लिए नया नहीं बना है। पंजाब नगर निगम विधेयक जो पंजाब की नगरपालिकाओं पर पहले से लागू है, केवल उसका विस्तारण करके, उसके क्षेत्र को विस्तृत करके चंडीगढ़ पर लागू कर दिया गया है। तो जो मूल बिल है पंजाब म्यूनिस्पल कार्पोरेशन लॉ, उसमें मनोनयन का कहीं कोई प्रावधान नहीं है और मैं यह भी आपकी जानकारी के लिए बतादूं कि वह जो मूल एक्ट है उसके तहत लुधियाना और जालंधर जैसे तीन बड़े नगर निगम कार्य कर रहे हैं और बिना सदस्यों को मनोनीत किए वहां काम बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, तो चंडीगढ़ के लिए यह नई प्रथा क्यों डाली जा रही है? चंडीगढ़ के लिए यह नई धारा क्यों जोड़ी गई है? मैं पूछना चाहती हूं गृह मंत्री जी से कि क्या चंडीगढ़ के लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों पर आपको विश्वास नहीं है? क्या चंडीगढ़ के लोग अपने तौर पर प्रशासन चलाने में असक्षम हैं? आखिर यह क्यों 9 सदस्यों का मनोनयन चंडीगढ़ नगर निगम के लिए किया जा रहा है? मेरी दूसरी बात यह है कि यह जो 9 सदस्य मनोनीत होंगे, उनको बिल्कुल निर्वाचित सदस्यों के बराबर अधिकार दिए गए हैं। मेयर चुनने के समय भी यह सदस्य वोट डालने के अधिकारी हैं और मैं आपको एक सिनेरियो बताती हूं। यहां महिलाओं के बारे में भाई विनोद शर्मा ने एक सिनेरियो प्रस्तुत किया था। लेकिन मैं आपको एक सिनेरियो बताती हूं जिसके चलते इन 9 सदस्यों का मनोनयन करके किसी भी बहुमत वाली निर्वाचित पार्टी को हार में बदला जा सकता है।

किसी भी बहुमत वाली निर्वाचित पार्टी को अल्पमत में किया जा सकता है। इन्होंने 20 सदस्यों की बात की है। मान लीजिए आप 20 सदस्यों की निर्वाचित संख्या रखते हैं और 20 सदस्य चुनकर आते हैं। एक पार्टी जो सत्ता में है वह 7 लोग चुनकर लाती है और एक पार्टी जो आज विपक्ष में है, वह 13 लोग चुनकर लाती है। तो यह 13 और 7 का सिनेरियो बनता है चुने हुए लोगों से लेकिन चूंकि मनोनयन का अधिकार है और जिस तरह की प्रथाएं चल रही हैं और जिस तरह का आज सत्ताधारी लोगों का रवैया है, वह 9 लोगों का मनोनयन करते हैं अपनी मर्जी से। मेयर का चुनाव होता है तब यह 9 और 7 की संख्या मिलकर 16 हो जाएगी और वे 13 लोग जो जनता द्वारा चुनकर आए थे, वे अल्पमत में हो जाएंगे और 16 लोगों के बल पर सत्ताधारी दल के लोग अपना मेयर बनाकर ले जाएंगे।

मैं जब यह सिनेरियो आपके सामने रख रही हूं तो पूछना चाहती हूं कि बताइए यह अलोकतांत्रिक ढांचा नहीं तो और क्या है? यह एक हाथ से लोकतांत्रिक ढांचा देकर दूसरे हाथ से वापस लेने की बात नहीं है तो क्या है? इन 9 सदस्यों के बल पर आप नगर निगम चलाएंगे, बहुमत को अल्पमत में करेंगे, चुने हुए लोगों की जीत को हार में बदलने का काम करेंगे। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि यह जो प्रावधान है, यह बहुत अलोकतांत्रिक प्रावधान है और इस धारा का विरोध सत्ताधारी दल के लोगों ने भी किया है हालांकि उनके कारण दूसरे रहे हैं। विनोद जी ने इस आधार पर किया कि यह चंडीगढ़ के लोगों के प्रशासन चलाने पर टिप्पणी नहीं है तो क्या है? क्या इससे हम चंडीगढ़ के लोगों की नालायकी साबित नहीं कर रहे हैं? सिंगला जी ने इस आधार पर विरोध किया कि सदस्यों का मनोनयन कहां से होना चाहिए। वह चाहते हैं कि पंजाब से हो। उधर जगमोहन जी कहते हैं कि आप पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से पूछने का काम करेंगे अथवा नहीं? सिंगला जी तो चाह रहे हैं कि लोग पंजाब से आएं और उधर जगमोहन जी पंजाब और हरियाणा से लाने की बात कर रहे हैं। इस पर आपने गृह मंत्री का जवाब सुना होगा कि अगर मैं मुख्यमंत्रियों से पूछूंगा तो उस नगर निगम का क्या चरित्र बनेगा, यह मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं। उनकी बात को समझने वाले समझ गए हैं, जो न समझे वो अनाड़ी है।

मैं आपसे कहना चाहती हूं कि मेरे दोनों भाई जो उस तरफ बैठे हुए हैं, चूंकि वे ट्रेजरी बेचेंज में हैं इसलिए उन्होंने अमेंडमेंट पेश नहीं किया लेकिन वह अपने लोगों को कह सकते हैं कि हमने आपकी बात रखी जरूर थी लेकिन और कोई मौका नहीं था कुछ करने का। मेरा यह संशोधन आपके लिए मौका उपस्थित कर रहा है। मैं संशोधन वापस नहीं लूंगी चाहे गृह मंत्री कितना भी कहें। मैं संशोधन वापस नहीं लूंगी। इस संशोधन पर वोट होगा और अगर आपने चंडीगढ़ के प्रतिनिधियों की बात सच्चे मन से उनका प्रतिनिधि होने के नाते से रखी है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि जिस समय इस संशोधन पर वोट हो तो वे तमाम लोग जो डेमोक्रेसी के लिए प्रतिबद्ध हैं और वे तमाम लोग जो हिंदुस्तान के अंदर लोकतांत्रिक नगर निगम ढांचा चाहते हैं, वे लोग और खास तौर पर मेरे ये दोनों साथी जिन्होंने खुलकर

विरोध किया है इस प्रावधान का, वे सब लोग इस धारा के विरोध में वोट करें और यह धारा इस बिल से निकलनी चाहिए वरना चंडीगढ़ के लोग आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। आप यह धारा डालकर उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं और एक अलोकतांत्रिक काम कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगी कि बिल पर जब आप वोट डालें तो मेरे तमाम साथी इस धारा के खिलाफ वोट डालें।

श्री जगमोहन: मैं यहां क्लैरिफाई कर दूं कि मैंने यह पूछा था कि आपकी इंटेंशन क्या है, क्या आप पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से पूछेंगे? मैंने अपनी बात नहीं कही थी।

श्रीमती सुषमा स्वराज: उन्होंने बता दिया, आप तो समझ गए होंगे, आप तो अनाड़ियों में नहीं हैं। दूसरा मेरा संशोधन है, पंक्ति 28 में मैंने कहा है कि जहां आपने शब्द "20" लिखा है वहां पर इसकी जगह आप "30" कर दीजिए। इसके लिए मेरे पास ठोस तर्क है। महोदया, पहली बात तो मैं यह कहना चाहूंगी कि यह जो इन्होंने "20" शब्द लिखा है, इसमें एक घुंडी रखी है। मेरे पास दोनों ऐक्ट हैं जो पहले इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में और जिस रूप में वह पास हुआ। जिस रूप में वह इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें धारा 4 की उपधारा 3 की उपधारा 1 में लिखा था कि—

"(3) The Corporation shall be composed of the following members, namely:—

(i) Ten members to be directly elected, representing wards;...."

उसके नीचे जहां मेरा संशोधन है उसमें भी लिखा था—

"In the first proviso, for "forty and more than fifty", substitute "ten";

ये दोनों चीजें तर्कसंगत थीं। इन्होंने कहा था 10 लोग रखेंगे। जहां पंजाब लॉ में था 40 नॉट मोर दैन 50। अब जो बिल पारित हो कर आया है इस में उन्होंने नीचे बदल दिया—

"In the first proviso, for "forty and more than fifty", substitute "twenty";

10 की जगह 20 कर दिया लेकिन ऊपर जहां लिखा था—

"The Corporation shall be composed of the following members, namely:—"

वहां कुछ नहीं लिखा, वहां पर 20 नहीं लिखा। सिर्फ लिखा है मैंबर्स टु बी डाइरेक्टली इलेक्टेड। यह उनकी बदनियती को झलकाता है। अगर जैसे ऊपर लिखा था उसी तरह स्पैसिफाइ कर देते, ऊपर भी 20 और नीचे भी 20 तो ठीक था। इसमें लिखा है मैंबर्स टु बी डाइरेक्टली इलेक्टेड। इसका मतलब ये संख्या तय करेंगे कि उसकी अधिकतम सीमा तो तय कर दी कि 20 से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन 10 होगी, 12 होगी, 15 होगी, यह गुंजायश रहेगी।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: 5 भी हो सकती है।..

श्रीमती सुषमा स्वराज: 5 तो नहीं होगी, पहले 10 थी उससे कम क्यों करेंगे। लेकिन वह 20 से ज्यादा नहीं होगी। अगर इनकी नीयत पूरे तौर पर 20 रखने की थी तो कम से कम जो बिल पहले आया था जहां 10-10 शब्द लिखे थे उनकी जगह 20-20 कर देते। जहां नीचे 20 कर दिया लेकिन ऊपर नहीं किया। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि इस शब्द को स्पैसिफाइ कीजिए कि 20 की जगह इस को 30 किया जाए क्यों किया जाए इसको मैं बताना चाहती हूं।

इस समय चंडीगढ़ की जनसंख्या 1991 के सेंसस के अनुसार 6 लाख, 61615 थी। लेकिन वहां पर 47 सैक्टर हैं, 9 सैक्टर और डेवलप हो रहे हैं। 22 लेबर कालोनीज हैं। मैं ऐसा मानती हूं कि 20 हजार की जनसंख्या के ऊपर सीमित अधिकार वाले जन प्रतिनिधि जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। उन को गली, कूचों, की सफाई, नाली, ट्यूब लाइट भी टूट जाए तो लोग कहते हैं इसे ठीक करवा दो, सब कुछ उन को करना पड़ता है। इसलिए बड़े क्षेत्र होंगे तो वह ये काम नहीं कर सकेंगे। कहीं पानी नहीं है तो पानी का टैंकर भेज दो। तो ग्रासरूट लेवल से वह जुड़ा हुआ जनसेवक बड़ा क्षेत्र होने पर प्रभावी रूप से काम नहीं कर सकेगा। तो यदि हम चाहते हैं कि वह जनसेवक प्रभावी रूप से काम कर सके, जो हमें क्षेत्र छोटा रखना होगा। चूंकि आज तक वहां कोई किसी तरह की चुनी हुई संस्था नहीं है, वहां एम.एल.ए. भी नहीं है, वहां एम.पी. को सारा काम करना पड़ता है और अब एम.पी. बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, स्टैंडिंग कमेटी बनाने के बाद

और भी ज्यादा बिजी रहते हैं, तो सब काम जन सेवकों को करना पड़ेगा। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि अगर चंडीगढ़ के चुने हुए निगम पार्षदों को प्रभावी ढंग से काम करने देना है तो वहां कम से कम 30 प्रतिनिधि चुनकर जरूर जाएं। इसलिए मैं चाहूंगी कि इस को 30 कर दिया जाए और जो 9 मनोनीत सदस्य हैं वह हटा दें। 30 लोगों का नगर निगम होगा तो वह प्रभावी रूप से काम कर सकेगी और जनता की समस्याओं का हल कर सकेगा, उनकी भावनाओं को समझकर काम कर सकेगा। इस लिए इसी भावना के साथ मैंने अपने दोनों संशोधन प्रस्तुत किए हैं। मैं चाहूंगी कि इनको स्वीकार किया जाए।

SHRI S.B. CHAVAN: I don't think I need to give any kind of explanation on what the hon. Member has said. Since she has said that she is not amenable to any kind of logic, that she is not going to listen to anything, that she is going to press this motion for the vote of the House, and if that be the position, I don't think that it is necessary for me to explain and try to convince her. There are a large number of...

श्रीमती सुषमा स्वराज: मुझे लगा कि आप स्वीकार नहीं करेंगे इसलिए मैंने कहा। आप मेरे इन अमेंडमेंट को स्वीकार करने को तैयार हैं तो मैं.... (व्यवधान)

SHRI S.B. CHAVAN: I think, there can be nothing more distorting than what she has said just now. Whatever provisions, with the best of intentions, have been made, with the kind of distortion that you are quite capable of, you can do the same thing in a very harmful manner and that is also borne out by the kind of argument you have put forth. It is borne out by the kind of argument you have put forth. I can only assure you that while nominating the members it is not the intention of the Government to convert the majority into a minority. That is the only thing which I can say. And there is not reason why the Government should try to do this kind of a thing. I am sure the hon. Member will be convinced that when I increased the number from 10 to 20, the nominated members could also have been proportionately increased. But we did not do that because of the fact that 20 members had to be provided for special reasons. There were certain difficulties which the hon. Members in the Lower House brought to my notice, that we will be able to provide the minimum kind of thing that is required for running the Corporation in a good manner, and that is why I had to accept that kind of an amendment. But now to say that we have accepted it merely because we would like to convert the majority into a minority, is far from the truth and it is a most uncharitable interpretation.

That is the only thing I can say. I don't think I need to say anything more.

श्री सिकन्दर बख्त: सदर साहिबा, मेरी गुजारिश है कि जिस-जिस इदारे में, इंस्टीट्यूशन में नामिनेटेड मेम्बर रखे जाते हैं उन नामिनेटेड मेम्बर्स का जनरली इलेक्टेड मैम्बर्स के साथ तनासुब क्या होता है, क्या प्रोपोर्शन होता है? यह एक्स्ट्रा आर्डिनरी प्रोपोर्शन का नामिनेशन क्या है? ठीक है नामिनेशन का लफ्ज बड़ा वेग है। मैं कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता, इस किस्म के नामिनेशन का इजहार करके क्या-क्या हुआ है? लेकिन कहना चाहता हूं कोई रेशनल नामिनेशन का होता है या नहीं होता है? क्या तनासुब है चुने हुए लोगों का और नामिनेटेड लोगों का? यह मोस्ट एक्स्ट्रा आर्डिनरी सिच्युएशन चंडीगढ़ के म्यूनिसिपल इलेक्शन में क्यों रखी जा रही है।

†شری سکندر بخت: صدر صاحبہ میری گذارش ہے کہ جس جس ادارہ میں انسٹی ٹیوشن میں نامینیٹڈ ممبر رکھے جاتے ہیں ان نامینیٹڈ ممبرس کا جنرلی الیکٹیڈ ممبرس کے ساتھ تناسب کیا ہوتا ہے کیا بروپورشن ہوتا ہے یہ ایکسٹرا آرڈینری پروپورشن کا نامینیشن کیا ہے۔ ٹھیک ہے نامینیشن کا لفظ بڑا ویگ ہے۔ میں کوئی الزام نہیں لگانا چاہتا اس قسم کے نامینیشن کا اظہار کر کے کیا کیا ہوا ہے۔ لیکن کہنا چاہتا ہوں کوئی ریشنل نامینیشن کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ کیا تناسب ہے چنے ہوئے لوگوں کا اور نامینیٹڈ لوگوں کا۔ یہ موسٹ ایکسٹرا آرڈینری سچوایشن چنڈی گڑھ کے میونسپل الیکشن میں کیوں رکھی جا رہی ہے۔

†Transliteration in Arabic Script.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश): नामिनेटेड मेम्बर को नार्मली वोटिंग राइट नहीं होता है। क्योंकि आपने स्पेसिफिकली इसमें रखा है कि वोटिंग राइट है, यह इंटेन्शन स्पष्ट करता है। वरना नामिनेटेड मेम्बर सामान्यतः कहीं पर वोटिंग राइट नहीं रखता है। आपने स्पेसिफिक कहा है कि वोटिंग राइट होगा दैट शोस द इंटेन्शन।

श्रीमती सुषमा स्वराज: इंटेन्शन उनकी देखी जाती है जिनका पास्ट रिकार्ड ...(**व्यवधान**)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now I will' put to vote the amendments moved by Shrimati Sushma Swaraj. The question is:

(1) "That at page 6, lines 21 to 25 be *deleted.*"

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

(2) "That at page 6, line 28 *for* the word "twenty" the word "thirty" be *substituted."*

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Schedule to vote. The question is:

"That the Schedule stand part of the Bill."

The motion was adopted.

ic The Schedule was added to the Bill. Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI S.B. CHAVAN: Madam, I beg to move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now we will take—up I think this is the last item of business—the Statutory Resolution and the New Delhi Municipal Council Bill, 1994.

I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL ORDINANCE, 1994 (NO. 8 OF 1994)

PROMULGATED BY THE PRESIDENT ON THE 25TH MAY, 1994.

II. THE NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL BILL, 1994.

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली): महोदया, मैं निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हूं:

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 25 मई, 1994 को प्रख्यापित नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद आदेश, 1994 (1994 का संख्यांक 8) का निरनुमोदन करती है।"

महोदया, सबसे पहले मुझे यह बात कहनी है कि गृह मंत्री ने जिस तरीके से आर्डिनेंस लाने का समर्थन किया और भारतीय जनता पार्टी पर जो हम, आर्डिनेंसेज का विरोध करते हैं हम पर कैजुअल और कम्टैम्चुअस रिमार्क किया वह निन्दनीय है। होम मिनिस्टर को चाहिये तो यह था कि वह माफी मांगकर यहां पर आते। अच्छा तो यह था कि वे शर्मसार होकर इस आर्डिनेंस को यहां पर पेश करते। उन्होंने कहा कि भारत जनता पार्टी आमतौर पर हर आर्डिनेंस का विरोध करती है और रटी-रटायी चीजें कह रहे हैं। मुझे मालूम है कि यह आर्डिनेंस अगले मानसून सेशन में कहीं आ सकता था, मुझे मालूम है कि 31 मई को टाइम खत्म हो रहा था और जो कांस्टिट्यूशनल प्राविजन्स हैं, उसके अनुसार 31 मई के बाद यह आर्डिनेंस नहीं ला सकते थे।

[**श्री वी० नारायणसामी** पीठासीन हुए]

मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि आर्डिनेंस लाने के लिये कांस्टिट्यूशनल प्राविजन के आधार पर यह बहुत जरूरी था। परन्तु मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कान्स्टीट्यूशन बिल जो लाये थे वह 1 जून 1993 को आया था। 1 जून 1993 से 31 मई, 1994, तक वह क्या करते रहें संविधान में एक साल का समय दिया गया था कि एक साल के अंदर सारे राज्यों के बिलों को कांस्टिट्यूशन के मुताबिक कर दिया जाय। एक साल तक आप कहां रहे? इस बीच में चार सेशन हुए। जून 1993 से लेकर मई 1994 तक चार सेशन हुए। आपकी क्या मजबूरी थी? मैं जानता हूं कि आर्डिनेन्स आप नहीं ला सकते थे बिना हाउस को प्रौरोग किये हुए। लेकिन उसके पहले पिछले वर्ष विंटर सेशन हुआ, मानसून सेशन हुआ, उनके अंदर आप कुंभकर्णी नींद क्यों सोए रहे? आपने यह कहा कि आर्डिनेंस लाने की व्यवस्था धारा 123 में है। मैं जानता हूं कि 123 में आपको पावर है, उसके मुताबिक आप यहां पर यह बिल ला सकते हैं, आर्डिनेंस ला सकते हैं। उपसभापति महोदय, लेकिन ये